भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 996
जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है

पश्चिम बंगाल से जीएसटी राजस्व में गिरावट

996**. श्री सौमित्र खानः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय जीएसटी संग्रह में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में 4.6 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4 प्रतिशत हो गई है;
(ख) पश्चिम बंगाल में इस गिरावट के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं;
(ग) पश्चिम बंगाल से जीएसटी संग्रह में गिरावट को दूर करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के राजकोषीय स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यय पर इस राजस्व गिरावट के प्रभाव को समझने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार जीएसटी अनुपालन में सुधार करने और राजस्व संग्रह में गिरावट की प्रवृत्ति को उलटने के लिए अपने कर आधार का विस्तार करने में पश्चिम बंगाल को किस प्रकार से सहायता देने की योजना बना रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी हाँ महोदय। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक जीएसटी राजस्व में वृद्धि हो रही है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

सकल जीएसटी संग्रह **(करोड़ रूपये में)**	**वित्त वर्ष 19-20**	**वित्त वर्ष 20-21***	**वित्त वर्ष 21-22**	**वित्त वर्ष 22-23**	**वित्त वर्ष 23-24**	**वित्त वर्ष 24-25 (जनवरी 2025** *तक)**
राजस्व	43,386	39,694	47,899	58,060	62,613	55,268
वृद्धि%	9.1%	-8.5%	20.7%	21.2%	7.8%	6.7%

* कोविड-19 के कारण वृद्धि प्रभावित हुई
** इसी अवधि की तुलना में

जीएसटी राजस्व, अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थितियों और राज्य में खपत के पैटर्न सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। हालाँकि, इस संबंध में पश्चिम बंगाल के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग): सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, समय-समय पर जीएसटी में सुधार के लिए कई उपाय करती है, जैसा कि नीचे भाग (ङ) के उत्तर में विस्तृत रूप से बताया गया है।

(घ): उपर्युक्त आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): सरकार ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर जीएसटी में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ बी2सी आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई-वे बिल, आईटीसी मिलान, ई-इनवॉयस को अनिवार्य करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन-आधारित एनालिटिक्स की तैनाती, पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण, गैर-आयकर दाखिल कर्ताओं, आयकर दाखिल न करने वालों पर जांच कार्रवाई, जोखिम वाले करदाताओं पर लक्षित मूल्यांकन-आधारित कार्रवाई आदि कर अनुपालन में सुधार उपाय शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्र और राज्य प्राधिकरणों द्वारा डेटा एनालिटिक्स और अन्य आसूचना के माध्यम से फर्जी फर्मों का पता लगाने के लिए नियमित कार्रवाई की जाती है। अब तक, प्रवर्तन इकाइयों द्वारा की जा रही गतिविधियों और व्यापार करने में सुगमता को बनाए रखने के महत्व के संबंध में राज्य और केंद्रीय जीएसटी संगठनों के प्रवर्तन प्रमुखों के 2 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। मास्टरमाइंड का पता लगाने और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के उद्देश्य से, सीजीएसटी अधिनियम में पर्याप्त कानूनी प्रावधान हैं जो इस प्रकार हैं: -

i. कर चोरी या गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग की गई आईटीसी की राशि या गलत तरीके से लिए गए रिफंड की राशि के लिए दंड;
ii. फर्जी आईटीसी मामलों में शामिल करदाताओं के पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण;
iii. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी को ब्लॉक करना;
iv. सरकारी बकाया की वसूली के लिए संपत्ति/बैंक खातों आदि की अनंतिम कुर्की।

*****